भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

विषयः पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संबंध में दिसम्बर माह, 2022 का मासिक सारांश।

1. जल जीवन मिशन (जेजेएम)

22,61,285 परिवारों को कार्यशील घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए, जिससे वर्ष की शुरुआत में 8.73 करोड़ की तुलना में कुल संख्या 10.75 करोड़ हो गई। इस माह के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 5,053 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई, जिससे वित्त वर्ष 2022-23 में कुल जारी राशि 23,862 करोड़ रुपये हो गई। गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव और हरियाणा के सभी गांवों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित किया गया है जबकि वर्ष के दौरान गुजरात हर घर जल राज्य बन गया।

2. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण चरण - II (एसबीएम-जी)

इस माह के दौरान 3,21,372 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और 1,691 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 575.23 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। दिसंबर, 2022 के दौरान कुल 11,738 गाँवों को ठोस कचरा प्रबंधन सुविधाओं से कवर किए जाने तथा 18,845 गाँवों को तरल कचरा प्रबंधन के साथ कवर किए जाने की सूचना है।

दिसंबर, 2022 के माह के दौरान 25,163 गांवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस घोषित किया, जिससे दिसंबर, 2022 की शुरुआत में 22,857 की तुलना में कुल संख्या 1,58,569 हो गई। इस वर्ष के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव ने अपने सभी गांवों को ओडीएफ+ उत्कृष्ट घोषित किया।

3. गोबरधन

गोबरधन के तहत, इस माह के दौरान 16 परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना मिली थी, जिससे 31.12.2022 तक कुल संख्या 469 हो गई।

4. एसपीएम-एनआईडब्ल्यूएएस का उद्घाटन

माननीय प्रधान मंत्री ने 30 दिसंबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता के जोका में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान (एसपीएम-एनआईडब्ल्यूएएस) का उद्घाटन किया।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इस दिन संस्थान में 'पेयजल गुणवत्ता-समस्याएं और चुनौतियों' संबंधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की।

5. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी), 2023

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी), 2023 जो राज्यों, जिलों और ग्राम पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करने और एसबीएम-जी चरण II की प्रगति का पता लगाने के उद्देश्य से 2 नवंबर, 2022 को लॉन्च किया गया, के तहत ग्राम पंचायतें ओडीएफ प्लस पैरामीटर के संबंध में बेसलाइन ग्राम स्व-मूल्यांकन करती हैं। दिसंबर, 2022 के दौरान 5.25 लाख गांवों ने बेसलाइन ग्राम स्व-मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है।

इसके अलावा, डीडीडब्ल्यूएस द्वारा मास्टर प्रशिक्षुओं (ट्रेनर) के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी) 2023 के संबंध में उन्नमुखीकरण कार्यक्रम तैयार किया गया जो 6, 7 और 8 दिसंबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 1776 मास्टर प्रशिक्षुओं ने उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में भाग लिया।

6. जेजेएम के संबंध में समीक्षा बैठक

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 14 दिसंबर 2022 को राजस्थान में जेजेएम के कार्यान्वयन के संबंध में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसके अलावा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में 23 दिसंबर, 2022 को राजस्थान में जेजेएम के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।

सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने 21 दिसंबर, 2022 को 13 फोकस राज्यों में जेजेएम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। 2 फोकस राज्य अगले दिन 22 दिसंबर, 2022 को समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

21 राज्यों (2 फोकस राज्यों सहित) में जेजेएम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सचिव, डीडीडब्ल्यूएस की अध्यक्षता में 22 दिसंबर, 2022 को भी एक बैठक आयोजित की गई थी।

7. शौचालयों की रेट्रोफिटिंग और गोबरधन परियोजनाओं की कार्यक्षमता का आकलन के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जल गुणवत्ता, '**जल से सुरक्षा'** को अभियान के रूप में शुरू किया गया।

8. सीखने और ज्ञान साझा करने का माहौल तैयार करने, स्केलेवल और किफायती समाधान खोजने, सर्वोत्तम प्रथाओं और सफलता की कहानियों को साझा करने के अलावा, प्रयासों में चूक से बचते हुए बेहतर सहयोग और तालमेल के लिए पिछले साल शुरू की गई नई पहल, रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम (आरडब्ल्यूपीएफ) की इस माह के दौरान एक बैठक आयोजित की गई। वॉश क्रियाकलापों में मिलकर कार्य करने तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु भागीदारों के मार्गदर्शन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को मैप किया गया था।

9. जल एवं स्वच्छता में नवाचार/प्रौद्योगिकी/उत्पाद/समाधान/अनुसंधान की जांच के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में और सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) की सह-अध्यक्षता में 'तकनीकी समिति' की 7वीं बैठक का आयोजन किया गया। तकनीकी समिति ने वर्ष 2022 में 15 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

10. ओडीएफ प्लस घटकों (लाइटहाउस पहल) के कार्यान्वयन के लिए राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियों को समग्र पर्यवेक्षण तथा तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करने में कॉर्पोरेट्स को शामिल करने के लिए भारत स्वच्छता गठबंधन (आईएससी) के साथ सहयोग को आगे बढ़ाया गया।

लाइट हाउस पहल के प्रथम चरण में, 15 राज्यों में 75 ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है और ओडीएफ प्लस उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों के लिए डीपीआर तैयार की गई हैं।

11. चक्रीय अर्थव्यवस्था

इस विभाग को जैविक और सूखे कचरे की चक्रीयता के लिए नोडल के रूप में कार्य सौंपा गया था। गोलमेज (राउंड टेबल) में और अन्य हितधारकों तथा राज्य सरकारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। प्राप्त सिफारिशों को संकलित किया गया और रोडमैप/रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया। 23 दिसंबर 2022 को आयोजित सर्कुलर इकोनॉमी के संबंध में वीसी के दौरान रूपरेखा (रोडमैप) के बारे में एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें मंत्रिमंडल (कैबिनेट) सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शामिल हुए।

12. एसबीएम-जी के संबंध में सलाह

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 22.12.202 को एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि यदि स्थानीय परिस्थितियों/आवश्यकताओं के कारण कुछ विशिष्ट गाँवों/ग्राम पंचायतों जैसे दुर्गम इलाकों, बड़ी मात्रा में कचरे वाले अर्ध -शहरी क्षेत्रों आदि में, जहाँ परिवारों से कचरे का संग्रहण किया जाना और तिपहिया/बैटरी वाहनों के माध्यम से संग्रहण/पृथक्करण केंद्र तक ले जाया जाना व्यवहार्य न हो, ऐसे गांवों/ग्राम पंचायतों के लिए मूल आवश्यकताओं के अनुसार मोटरयुक्त वाहन खरीदे जा सकते हैं।

इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 28.12.2022 को एक सलाह भी जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि एसबीएम (जी) चरण-II की विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आबादी की औसत वार्षिक वृद्धि दर पर विचार करते हुए अनुमानित आबादी के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की गणना करनी चाहिए। इसके अलावा, उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले गांवों में जैसे कि अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, अगले 5 वर्षों अथवा इसके आस-पास में भावी वृद्धि को भी आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जा सकता है।

13. सीपीओ का उन्मुखीकरण

सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने 15.12.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों (सीपीओ) के लिए एसबीएम (जी) चरण- II से संबंधित एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम में 112 सीपीओ ने भाग लिया। इसमें मिशन निदेशक, आकांक्षी जिले, नीति आयोग ने भी भाग लिया।

14. दीवार कैलेंडर और मासिक समाचार पत्र

विभिन्न एसबीएम-जी घटकों से संबंधित उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और सूचना का प्रसार करने के लिए एसबीएम-जी वॉल कैलेंडर, 2023 तैयार किया गया है। दिसंबर 2022 माह के लिए एसबीएम-जी, डीडीडब्ल्यूएस का मासिक समाचार पत्र अर्थात "स्वच्छता समाचार" जारी किया गया।

*****